

(ख) सरकारी अस्पतालों में उपस्करों का रख-रखाव और मरम्मत एक सतत प्रक्रिया है। जब कोई उपचार खराब हो जाता है तो संबंधित संस्था/अस्पताल द्वारा वार्षिक सेवा संविदा पर मुख्यतः निर्भर करते हुए यथाशीघ्र संभव समय में मरम्मत कराई जाती है।

पब्लिक स्कूलों पर सरकार का नियंत्रण

533. प्रो. रामगोपाल यादव :

श्री ईश दत्त यादव :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का पब्लिक स्कूलों पर कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नियंत्रण है,

(ख) यदि हां, तो अदालती आदेश की खुली अवहेलना कर जबरन फीस के रूप में मोटी रकम वसूलने के खिलाफ क्या सरकार उच्च न्यायालय के आदेश का पालन करने हेतु तत्काल कोई कदम उठाएगी जिसमें मध्यम एवं सामान्य वर्ग के लोगों को राहत मिल सके, और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) पब्लिक स्कूलों पर नियंत्रण संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य प्रशासन के शिक्षा अधिनियम में किये गये उपबंधों के अनुसार और उस बोर्ड के संबंधित उपनियमों के अनुसार किया जाता है जिससे स्कूल संबद्ध होते हैं।

(ख) और (ग) शुल्क इत्यादि लेने के संबंध में उच्च न्यायालय द्वारा किये गये आदेशों के कार्यान्वयन से संबंधित प्रश्न संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य प्रशासन के कार्यक्षेत्र में आता है। केन्द्रीय सरकार को ऐसे कोई निर्देश उच्च न्यायालय से नहीं प्राप्त हुए हैं।

तकनीकी शिक्षा का विकास

534. श्री बालकवि बैरागी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1996-97, 1997-98 और 1998-99 के दौरान राज्य सरकारों ने अपने-अपने राज्यों में तकनीकी शिक्षा एवं तकनीकी उच्च शिक्षा के विकास के

लिए केन्द्र सरकार को कौन-कौन सी योजनाएं प्रेषित की हैं,

(ख) उनके द्वारा उक्त योजनाओं के लिए केन्द्र सरकार से मांगी गई राशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है,

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा कौन-कौन से राज्यों की कौन-कौन सी योजनाओं को कितनी-कितनी राशि की स्वीकृति प्रदान की गई है और केन्द्र सरकार द्वारा राज्यवार कितनी सहायता प्रदान की गई है, और

(ग) स्वीकृति के लिए विचाराधीन योजनाएं राज्यवार कौन-कौन सी शेष हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (घ) तकनीकी शिक्षा परियोजना 1 तथा 2 के अंतर्गत, भारत में पॉलिटेक्निक शिक्षा का उन्नयन करने के लिए 19 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का एक कार्यान्वयनाधीन परियोजना के तहत विश्व बैंक द्वारा निधियां प्रदान की गई है।

इस परियोजना के तहत पॉलिटेक्निक शिक्षा में प्राप्त लाभों के कायम रखने लिए इस मंत्रालय ने तकनीकी शिक्षा परियोजना नामक एक अन्य परियोजना के लिए नई विदेशी सहायता का प्रस्ताव किया है जिसमें लगभग लगभग 10 चुनिंदा पॉलिटेक्निकों को उत्कृष्टता के केन्द्रों में बदलने, कुछ भारतीय पॉलिटेक्निक संस्थानों की स्थापना करने और कार्यान्वयनाधीन परियोजना के तहत शामिल न किये गये राज्यों को शामिल करने का कार्य निहित है। विभिन्न राज्य सरकारों से मांगी गई निधियों की आवश्यकता के अनुमानों के आधार पर एक समेकित परियोजना प्रस्ताव विश्व बैंक से सहायता की मांग करने के लिए तैयार कर लिया गया है।

Drop out Rate

535. DR. (Ms.) P. SELVIE DAS: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) how many children in the age groups 6—10 and 11—13 years, were out of school in the Eighth Five Year Plan period State-wise and sex-wise; and

(b) the number of children dropped out by the age of 10 years, sex-wise and state-wise?

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DR. MURLI MANOHAR JOSHI):